गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 168
दि. 17.10.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल — सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, आज होगा नया कैबिनेट विस्तार

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात की राजनीति में शुक्रवार का दिन बेहद अहम साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली पूरी राज्य कैबिनेट ने गुरुवार देर रात सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे राजभवन में नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। यह कदम भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन और सरकार दोनों में नई ऊर्जा और संतुलन लाने की कोशिश कर रही है। भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने दिसंबर 2022 में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, अब अपने कार्यकाल के लगभग तीन साल पूरे करने जा रहे हैं। इतने लंबे समय में मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए यह फेरबदल भाजपा की "युवा और परफॉर्मेंस आधारित" रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस बार मंत्रिमंडल में लगभग दस नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जबकि आधे से ज्यादा पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भाजपा संगठन की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि केवल वही मंत्री रहेंगे, जिनका प्रदर्शन जनता और पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है।

नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ नेताओं को भी जगह मिल सकती है। इनमें अर्जुन मोढवाड़िया, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और सी.जे. चावड़ा के नाम प्रमुख हैं। इन नेताओं को शामिल करने के पीछे भाजपा का उद्देश्य है कि कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक — पाटीदार,

ओबीसी और उत्तर गुजरात के ठाकोर समुदाय — को साधा जा सके। साथ ही सौराष्ट्र क्षेत्र के जयेश रादडिया और जीतू वाघानी जैसे पुराने लेकिन लोकप्रिय चेहरों को भी मंत्रिमंडल में पुनः लाया जा सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के इस कदम के पीछे चार प्रमुख कारण हैं।

पहला, तीन साल से कोई बदलाव नहीं हुआ था। भाजपा हर चुनाव से पहले संगठन और सत्ता दोनों में ताज़गी लाने की परंपरा निभाती रही है।

दूसरा, कई मंत्रियों के कामकाज को लेकर पार्टी आलाकमान संतुष्ट नहीं था। हाल ही में विसावदर उपचुनाव में भाजपा को झटका लगा था, जहाँ मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व के बावजूद पार्टी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया से हार गई। तीसरा, पुराने दिग्गजों को फिर से सक्रिय करने की योजना है। कई प्रभावशाली नेता लंबे समय से किनारे थे, उन्हें अब नए जिम्मेदारी भरे पद दिए जा सकते हैं ताकि असंतोष को दूर किया जा सके।

और चौथा, सत्ता-विरोधी लहर को रोकना। गुजरात में यह परंपरा रही है कि जब भी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ने लगता है, भाजपा नेतृत्व तुरंत चेहरे बदलकर नई टीम पेश कर देता है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल से ही यह "रोकथाम वाली रणनीति" भाजपा की पहचान रही है — चाहे आनंदीबेन पटेल हों या विजय रूपाणी, दोनों के कार्यकाल इसी तरह अचानक समाप्त हुए थे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बार दो उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, ताकि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित किया जा सके। एक डिप्टी सीएम उत्तर गुजरात से और दूसरा सौराष्ट्र से होने की संभावना जताई जा रही है।

इस बड़े फेरबदल के बाद भाजपा आने वाले नगर पंचायत और जिला परिषद चुनावों पर पूरा फोकस करेगी। पार्टी चाहती है कि राज्य की नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तालमेल मजबूत हो, ताकि आने वाले दो वर्षों में जनता के बीच ठोस विकास कार्यों का असर दिखे।

गुजरात में होने जा रहे इस बदलाव को राजनीतिक हलकों में "मिनी रि-शफल" नहीं, बल्कि "2027 की बड़ी तैयारी" के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नज़र शुक्रवार सुबह 11:30 बजे होने वाले शपथग्रहण समारोह पर टिकी है, जहाँ यह तय होगा कि भाजपा का नया चेहरा कैसा होगा और किनके सिर पर मंत्रीपद का ताज सजेगा।

रेलवे में सफाई की दिशा में बड़ा कदम अब एसी यात्रियों को मिलेगा कंबल के साथ प्रिंटेड कवर, जयपुर-असर्वा एक्सप्रेस से हुई शुरुआत

(जीएनएस)। नई दिल्ली/जयपुर। भारतीय रेल ने सफाई और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम पहल की है। अब एसी कोचों में यात्रियों को कंबल के साथ एक स्वच्छ प्रिंटेड कवर दिया जाएगा। यह सुविधा फिलहाल जयपुर-असर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12981) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को राजस्थान के खातीपुरा जयपुर रेलवे स्टेशन से इसका औपचारिक शुभारंभ किया। रेल मंत्री ने बताया कि यह प्रोजेक्ट यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अक्सर यात्रियों की ओर से यह शिकायत आती थी कि ट्रेन के एसी कोच में दिए जाने वाले कंबल या बेडरोल से बदबू आती है या वे ठीक से साफ नहीं होते। इस समस्या के समाधान के लिए अब हर यात्री को एक ताजे और प्रिंटेड कवर में बंद कंबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे पूरे देश में सभी प्रमुख ट्रेनों में लागू किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा, "कंबल का उपयोग रेलवे में सालों से होता आ रहा है, लेकिन सफाई पर संदेह बना रहता था। अब यह पहल उस संदेह को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यात्री अब और अधिक स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल में यात्रा कर सकेंगे।" जयपुर-असर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस राजस्थान की प्रमुख ट्रेनों में से एक है, जो जयपुर से असर्वा तक लगभग 11 घंटे 55 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करती है। ट्रेन में एसी वन, टू और थ्री टियर कोच हैं, और नए कवर से यात्रियों को विशेषकर सर्दियों के मौसम में अधिक आराम मिलेगा।

रेल मंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर डिवीजनों के लिए कई अन्य यात्री सुविधाओं की भी शुरुआत की। इनमें छोटे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाना, नए साइनबोर्ड लगाना, और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुरू करना शामिल है। गौरतलब है कि साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रेलवे ने एसी कोचों में पर्दे, चादर और कंबल देने की सुविधा को दो साल के लिए बंद कर दिया था। यात्रियों को केवल डिस्पोजेबल बेडरोल पैसे देकर उपलब्ध कराया जाता था। अप्रैल 2022 में यह सेवा दोबारा शुरू की गई थी, लेकिन अब इस नई पहल के बाद यात्रियों को और अधिक स्वच्छता और सुविधा का अनुभव मिलेगा। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि प्रिंटेड कवर नियमित रूप से धोए और बदले जाएंगे, जिससे कंबल की सफाई पर यात्रियों का भरोसा कायम रहेगा। यह पहल भारतीय रेल की 'स्वच्छ यात्रा अभियान' के तहत एक और सकारात्मक कदम मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाना है।

पंजाब में बड़ा भ्रष्टाचार खुलासा — डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार, घर से बरामद हुए करोड़ों रुपये नकद

(जीएनएस)। चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर को गुरुवार दोपहर सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई फतेहगढ़ साहिब के एक स्क्रैप कारोबारी की शिकायत पर की गई, जिसने आरोप लगाया था कि डीआईजी ने एक मामले को "सुलझाने" के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने जाल बिछाकर अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया, जब वह रिश्वत की रकम स्वीकार कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, यह ट्रैप ऑपरेशन मोहाली स्थित उनके कार्यालय में अंजाम दिया गया। कारोबारी को डीआईजी ने पहली किस्त देने के लिए वहीं बुलाया था। जैसे ही उसने पैसों से भरा बैग सौंपा, सीबीआई की टीम ने मौके पर धावा बोल दिया और आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि वे मामलों में रियायत देने या जांच को प्रभावित करने के एवज में धन की मांग करते थे।

एजेंसी ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद पूरी योजना बनाकर यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई ने डीआईजी के सरकारी आवास और निजी ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस दौरान जांचकर्ताओं को 3 बैग और 1 अटैची में भरी हुई भारी मात्रा में नकदी मिली। शुरुआती गिनती में यह रकम कई करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका है। सीबीआई टीम ने सभी नकदी, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह रकम किन स्रोतों से आई और क्या इसमें अन्य अफसरों या मध्यस्थों की भूमिका रही है। डीआईजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है।

इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का इस तरह रिश्वत लेते पकड़ा जाना राज्य की प्रशासनिक साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

समुद्री सुरक्षा पर मंडराता डिजिटल खतरा — नौसेना प्रमुख ने चेताया साइबर हमलों से सतर्क रहने को

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने वैश्विक समुद्री क्षेत्र में बढ़ते साइबर खतरों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक ने जहां नौसेना की कार्यक्षमता और रणनीतिक क्षमता को कई गुना बढ़ाया है, वहीं इसने सुरक्षा के नए आयामों में भी गहरी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

नई दिल्ली में आयोजित एक साइबर सुरक्षा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि समुद्री जगत अब पारंपरिक सीमाओं से आगे निकलकर एक डिजिटल महासागर में बदल चुका है। उन्होंने चेताया कि आज के दौर में हर पोत, बंदरगाह और नेविगेशन सिस्टम केवल एक जहाज नहीं, बल्कि "तैरता हुआ नेटवर्क" बन चुका है — जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड आधारित प्रणालियों पर निर्भर है। ऐसे में कोई भी साइबर हमला सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन सकता है। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि "डिजिटल क्रांति ने हमें दक्षता, सटीकता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता दी है, लेकिन इसी क्रांति ने हमारे लिए 'नई कमजोरियां' भी पैदा की हैं। स्मार्ट पोर्ट्स, स्वायत्त जहाज, एआई-आधारित लॉजिस्टिक्स — ये सब हमारी ताकत हैं, परंतु इन्हें सुरक्षित रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है।" उन्होंने कहा कि भारत का समुद्री नेटवर्क विशाल है — इसमें 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा, 200 से अधिक बंदरगाह और लाखों नौवहन उपकरण शामिल हैं। यदि इनमें से किसी एक प्रणाली पर साइबर हमला होता है, तो उसका असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला और नौसैनिक अभियान तीनों पर पड़ सकता है।

नौसेना प्रमुख ने बताया कि नौसेना ने पहले ही एक समर्पित साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ (Cyber Operations Division) स्थापित किया है, जो लगातार जहाजों, पनडुब्बियों और कमांड नेटवर्क की निगरानी करता है। उन्होंने कहा कि "सुरक्षा का अर्थ अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा भी है। आने वाले समय में युद्ध केवल समुद्र, वायु या अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़े जाएंगे।"

एडमिरल त्रिपाठी ने यह भी कहा कि भारत को "साइबर समुद्री संप्रभुता" (Cyber Maritime Sovereignty) की अवधारणा को अपनाना होगा, जिसमें स्वदेशी सॉफ्टवेयर, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क और सुरक्षित उपग्रह संचार का व्यापक उपयोग किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी, नौसैनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक संयुक्त साइबर रेजिलिएंस नेटवर्क बनाया जाए, ताकि किसी भी संभावित साइबर हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। संगोष्ठी में रक्षा मंत्रालय, नौसेना और उद्योग जगत के कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और इस बात पर सहमति जताई कि आने वाले वर्षों में समुद्री क्षेत्र केवल जहाजों की ताकत से नहीं, बल्कि डेटा सुरक्षा और साइबर क्षमता से भी परिभाषित होगा।

कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज परिसरों में आरएसएस गतिविधियों पर रोक लगाने की तैयारी — मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, नया कानून जल्द लागू होगा

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में एक नए नियम को लाने पर सहमति बनी। यह कदम राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव से मुक्त रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्री प्रियांक खरगे ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल व कॉलेज परिसर में आरएसएस की बैठकें, शाखाएं या अन्य प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित नहीं की जा सकेंगी। सरकार जल्द ही इस निर्णय को कानूनी रूप देने के लिए नया अधिनियम लाएगी।

प्रियांक खरगे ने बताया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी मंदिरों में आरएसएस जैसी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह संगठन युवाओं के विचारों को प्रभावित कर "संवैधानिक मूल्यों के विपरीत दिशा में" काम कर रहा है।

मंत्री ने कहा कि "हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को स्वतंत्र सोच, तर्कशक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाने के लिए है, न कि किसी विशेष विचारधारा को थोपने के लिए। इसलिए हमने तय किया है कि सरकारी परिसरों को राजनीतिक और वैचारिक गतिविधियों से मुक्त रखा जाएगा।"

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी हाल ही में यह कहा था कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि कोई भी संगठन या समूह सार्वजनिक या सरकारी संस्थानों में अपनी विचारधारा थोपकर लोगों को परेशान न करे। उन्होंने कहा था कि "राज्य का प्रशासन धर्मनिरपेक्ष और समावेशी रहेगा — किसी भी समूह को संस्थानों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" इस बीच, मंत्री प्रियांक खरगे को इस प्रस्ताव के बाद धमकी भरे फोन कॉल मिलने लगे थे। बेंगलुरु पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। पुलिस के अनुसार, प्रियांक खरगे ने उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसके आधार पर सदाशिवनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और कलबुर्गी पुलिस की मदद से आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

कर्नाटक में यह निर्णय राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। जहां कांग्रेस सरकार का तर्क है कि शिक्षा संस्थानों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक या वैचारिक गतिविधि से मुक्त रखना लोकतांत्रिक दायित्व है, वहीं विपक्षी दल भाजपा ने इस निर्णय को "विचारधारा विरोधी और असंवैधानिक" बताया है।

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच पर सवाल, पायलट के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट बोले "सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं"

(जीएनएस)। अहमदाबाद। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दर्दनाक हादसे की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े तक पहुंच गई है। हादसे में मारे गए पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल और इंडियन पायलट्स फेडरेशन ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच प्रक्रिया पर गहरा अविश्वास जताया और कोर्ट की निगरानी में नई जांच की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि AAIB की जांच पक्षपातपूर्ण और अधूरी है, जिसमें कई तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं

की अनदेखी की गई है। सभरवाल परिवार का कहना है कि पायलट को दोषी ठहराना बिना ठोस सबूतों के जल्दबाज़ी में लिया गया निष्कर्ष है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि दुर्घटना की जांच किसी स्वतंत्र टीम से कराई जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो और टीम में अंतरराष्ट्रीय एविएशन विशेषज्ञ शामिल किए जाएं ताकि तथ्यात्मक सच्चाई सामने आ सके।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिवाली के बाद सुनवाई करने का फैसला किया है। अदालत यह तय करेगी कि क्या मौजूदा जांच एजेंसी से जांच वापस लेकर स्वतंत्र निगरानी समिति को सौंपी जाए या नहीं।

एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था। टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। इस भीषण हादसे में 270 लोगों की जान चली गई, जिनमें पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल और को-पायलट क्लाइव कुंदर भी शामिल थे। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट, जो 12 जुलाई को जारी की गई थी, में कहा गया कि "फ्यूल कट-ऑफ स्विच" गलती से ऑफ कर दिया गया था, जिससे इंजन बंद हो गए और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि कॉकपिट की वॉयस रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि स्विच ऑफ क्यों किया गया। याचिका में इस रिपोर्ट को "अधूरी और भ्रामक" बताया गया है। पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल ने कहा, "मेरा बेटा सुमीत एक अनुभवी और प्रशिक्षित पायलट था। उसने हजारों उड़ानें बिना गलती के संचालित कीं। जिस तरह उसे दोषी ठहराया गया है, वह न्याय के साथ मज़ाक है। हमें विश्वास है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो सच्चाई सामने आएगी और यह साबित होगा कि हादसा तकनीकी खामी या ग्राउंड कंट्रोल की गलती से हुआ था।" इंडियन पायलट्स फेडरेशन ने भी AAIB की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि सरकारी जांच एजेंसियां अक्सर पायलटों को बलि का बकरा बना देती हैं ताकि सिस्टम की खामियों और मैनेजमेंट की लापरवाही से ध्यान हटाया जा सके। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जो दिवाली के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद ⇌ शेखपुरा के बीच त्यौहार विशेष ट्रेन चलायी जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियाँ	प्रस्थान	आगमन
09463	अहमदाबाद - शेखपुरा	18.10.2025 एवं 23.10.2025	15:20 बजे	04:00 बजे (तीसरा दिन)
09464	शेखपुरा - अहमदाबाद	20.10.2025 एवं 25.10.2025	06:30 बजे	20:00 बजे (दुसरे दिन)

होल्टः नडियाद, आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, संत हिरदाराम नगर, बीना, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्ज़ापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया जंक्शन, तिलैया और नवादा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में।

संरचना: एसी द्वितीय श्रेणी, शयनयान और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे।

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन संख्या 09463 की बुकिंग 17.10.2025 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। उपरोक्त ट्रेन विशेष किराए पर विशेष ट्रेन के रूप में चलायी जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly
हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly
हमें फॉलो करें: Instagram/WesternRly

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ लाएँ।

संपादकीय

विकास दर की लय

जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पर पश्चिमी शक्तियों के मंसूबों के अनुरूप सुर में सुर मिलाने का आक्षेप लगता रहा है, यदि वह अब भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर दर्शाए तो इसे हम अपनी आर्थिकी की ताकत के रूप में देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ ने वर्ष 2025-26 के लिये भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। इस नवीनतम अपडेट से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में देश की स्थिति और मजबूत हुई है। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह संशोधन लचीली घरेलू खपत, मजबूत सेवा निर्यात और स्थिर सार्वजनिक निवेश के दृष्टिगत किया है। यह सुखद ही कहा जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने और भारी-भरकम टैरिफ का कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। लेकिन इस आशावाद के बावजूद हमें अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य की वास्तविकता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिसके मूल में तमाम व्यापारिक व्यवधान, अमेरिकी टैरिफ वृद्धि और सख्त वित्तीय स्थितियों जैसे घटक भी शामिल हो सकते हैं। जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कहीं न कहीं भारत की आर्थिक गति को प्रभावित कर सकते हैं। निर्विवाद रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में आईएमएफ का भरोसा, मजबूत भारतीय घरेलू बाजार, राजकोषीय अनुशासन और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के उद्देश्य से किए गए सुधारात्मक उपायों के चलते जगा है। वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे पर खर्च, डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहन और बेहतर कर संग्रह ने व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत ही किया है। हालांकि निर्यात, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, संरक्षणवादी नीतियों और कमजोर वैश्विक मांग के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर चीन की मंदी और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्संतुलन के साथ, भारत के सामने चुनौती और अवसर दोनों ही मौजूद हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाते हुए आत्मनिर्भरता की राह में कदम आगे बढ़ाए। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौती को महसूस करते हुए 'मेक इन इंडिया' की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास एक आंदोलन के रूप में किया है। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत विनिर्माण पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की प्राथमिकता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सेमीकंडक्टर और हरित प्रौद्योगिकियों के लिये लक्षित प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना है। निस्संदेह ये प्रयास कालांतर देश के औद्योगिक आधार को व्यापक रूप से मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अल्पकालिक लक्ष्यों के बजाय दीर्घकालीन जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। इसके लिये जरूरी है कि श्रम बाजार, भूमि अधिग्रहण में सुधार और व्यापार में कामकाज को आसानी को बढ़ावा दें। निस्संदेह, इन क्षेत्रों में गहन संरचनात्मक सुधारों की सख्त आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की प्राथमिकता मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की भी होनी चाहिए। महंगाई के बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है, जिससे मांग व पूर्ति का संतुलन बिगड़ता है। वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादकता और रोजगार सृजन को भी नीतिगत एजेंडे के केंद्र में रखना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि आज भारत की आर्थिक सफलता की कहानी हमारे सतर्क आत्मविश्वास की परिणति है। देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के लचीलेपन ने इसे कई बाहरी झटकों से बचाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी आत्मसंतुष्टि इस लाभ को कम सकती है। इसके अलावा दीर्घकालिक स्थिरता के लिये, भारत सरकार को राजकोषीय विवेक बनाए रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ मानव पूंजी, उत्पादकता और नवाचार में निवेश को बढ़ाना होगा। निस्संदेह, हमारा विकास तभी सार्थक होगा जब वह समावेशी हो। वह देश के लाखों गरीब लोगों को ऊपर उठाने में सक्षम हो, न कि केवल सिर्फ सांख्यिकीय संकेतकों को बढ़ावा देने वाला हो। हमारी आर्थिक यात्रा में निरंतर स्थिरता बनी रहे, इसके लिये देश को आर्थिक सुधार की राह चुननी होगी ।

आरटीआई कानून को प्रभावकारी बनाने की जरूरत

> "आरटीआई कानून शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है जो लोकतंत्र की जरूरत भी है। आवेदन करने में बाधाओं के बावजूद अब वेबसाइट लिंक मुहैया होना सकारात्मक पहलू है। बेशक कुछ संशोधनों से सूचना आयोगों पर असर पड़ा है। पूरे 20 साल पुराने इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए लोगों को आगे आना होगा।

भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त होने के नाते मुझे राजस्थान स्थित ब्यावर में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हुए समारोह में आमंत्रित किया गया, वह शहर जहां 1996 में इस प्रकार का कानून बनाए जाने के समर्थन में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था। अपने संबोधन की शुरुआत मैंने गुरुदत्त की क्लासिक फ़िल्म 'कागज़ के फूल' के गीत की पंक्तियों से की—'वक़्त ने किया क्या हसीं सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम...।'

अब जबकि 2005 में आए इस अधिनियम की सालगिरह मनाई जा रही है, इसको लेकर गर्मागर्म बहसें भी चली हुई हैं, अक्सर भावनात्मक, यह क्या फायदे लेकर आया और क्या चुनौतियां भी। कहा जा सकता है कि 2014 के राष्ट्रीय चुनावों में यह उसी सरकार को मुश्किल में डालने के कारणों में से एक रहा, जिसने इस अधिनियम को लागू किया था। अगली सरकार ने घोषित तौर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत को बरकरार रखने की बात कही और प्रशासन एवं सरकार की पहचान अलग रखने का प्रयास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के अपने चुनाव अभियान में 'पारदर्शिता अधिकतम और प्रशासनिक अड़ंगे न्यूनतम' रखने का वादा किया था–'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देकर प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ाने का वादा।

फिर भी, जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने हाल ही में ब्यावर में आयोजित एक आरटीआई मेले में अपने संबोधन में उल्लेख किया है, कानून में संशोधन और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए कानून के पारित होने के कारण सूचना आयुक्तों का अधिकार क्षेत्र घटा है और यह सूचना आयोगों की स्वतंत्रता में भी ह्रास करने वाला है। आगे, आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में भी एक संशोधन किया गया है, जिसमें सार्वजनिक हित स्थापित होने पर निजी मानी जाने वाली जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति थी। इसलिए, यह अधिनियम शासन की प्रकृति के संदर्भ में परिवर्तनकारी रहा।

यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि लोकतंत्र में सरकार का सार तत्व पारदर्शिता है, ताकि प्रत्येक अंग - कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका- नागरिक के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन जहां तक भारत में नौकरशाही की मानसिकता का प्रश्न है, 'माई-बाप' वाली सामंती सोच गणतंत्र के जन्म के बाद भी लंबे समय तक कायम है।

सूचना का अधिकार अधिनियम घोषित करता है कि लोकतंत्र के लिए एक जागरूक नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता होना आवश्यक है, जो इसके संचालन के लिए तो अत्यंत आवश्यक है ही, साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, सरकारों एवं उनके तंत्रों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए भी जरूरी है। इस प्रकार, यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को शासन में प्रमुख भागीदार बनाने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कानून शासन को अत्यधिक सुदृढ़ बनाने में एक माध्यम है। दो प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों - सूचना का अधिकार आकलन एवं विश्लेषण समूह (आरएएजी) और जन सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान - ने अपनी जन आकलन रिपोर्ट (2008) में 11 राज्यों से प्राप्त फीडबैक के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर पाया कि आरटीआई अधिनियम को लेकर जागरूकता स्तर, अपने प्रारंभिक चरण में किसी भी अन्य कानून के बारे में जागरूकता की तुलना में काफी ऊपर था। सर्वे में भाग लेने वाले 40 प्रतिशत से अधिक शहरी उत्तरदाताओं को इस अधिनियम के बारे में जानकारी थी, हालांकि ग्रामीण उत्तरदाताओं में यह आंकड़ा 20 फीसदी से भी कम था। ग्रामीण भारत में जागरूकता के स्रोत में : समाचार पत्र (35 प्रतिशत), टेलीविजन एवं रेडियो, दोस्त-रिश्तेदार (प्रत्येक 10 प्रतिशत), और एनजीओ (5 प्रतिशत) थे। शहरी क्षेत्र के लोगों में सजगता का मुख्य स्रोत समाचार पत्र (30 प्रतिशत), एनजीओ (20 प्रतिशत), टीवी (20 प्रतिशत) दोस्त और रिश्तेदार (10 प्रतिशत) था।

नकारात्मक पहलू यह पाया गया कि प्रशासनिक अड़चनें आवेदन दाखिल करने में अड़ंगा डालती रहीं। यह मुश्किल इस तथ्य से और बढ़ गई कि देश भर में अधिनियम को लागू करने के लिए आरटीआई नियमों के 114 अलग-अलग सेट थे और ऐसी कोई एक जगह नहीं थी जहां वे सभी सुलभ हों। कुछ राज्यों ने तो अधिनियम की धारा 4(4) के बावजूद केवल स्थानीय भाषा में पत्राचार पर जोर दिया, जबकि उक्त धारा कहती है: आवश्यक है कि सूचना 'उस क्षेत्र में संचार की सबसे प्रभावशाली विधि' द्वारा प्रदान की जाए। ये आरंभिक कठिनाइयां काफी हद तक काबू कर ली गयी हैं और आज हरेक केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों के विभाग इस अधिनियम के तहत अपने यहां इसके लिए अनिवार्य वेबसाइट लिंक होने पर गर्व कर सकते हैं। राजस्थान में इसके लिए 'जन सूचना' तो कर्नाटक में 'माहिती कनाजा' पोर्टल हैं, जो उन सभी सरकारी विभागों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे उन सूचनाओं के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने की जरूरत से छुटकारा मिल जाता है, जिन्हें कानून सामान्य मानता है लेकिन औसत उपभोक्ता के लिए रोजमर्रा के काम की हैं।

सार्वजनिक प्राधिकरणों पर आरटीआई अधिनियम के प्रभाव पर निष्कर्षों के आकलन में, 2006 की रिपोर्ट में पाया गया कि 20 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण और 45 प्रतिशत शहरी पीआईओ (लोक सूचना अधिकारी) ने दावा किया कि कानून के कारण उनके कार्यालयों के कामकाज में बदलाव आए हैं। इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन रिकॉर्ड रखरखाव में सुधार से संबंधित थे, जैसा कि मैंने स्वयं हमारे सबसे कार्यकुशल माने जाने वाले कार्यालयों के नाना विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए पाया था, जोकि पहले एक घोर उपेक्षित क्षेत्र था।

दिलचस्प यह कि तब तक, ग्रामीण कार्यालयों में से 10 प्रतिशत और शहरी सार्वजनिक प्राधिकरणों में से 25 फीसदी ने कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बदलाव अपनाकर, उन्हें आरटीआई के अनुरूप बना लिया था। तब से यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया होगा। फिर भी, साझा की जाने वाली जानकारी, कम से कम केंद्र सरकार के संदर्भ में, जनता की ज़रूरत की बजाय, सरकारी सफलताओं का दिखावा ज़्यादा लगती है।

सूचना के अधिकार को भारत के लोगों के लिए वास्तविक बनाने में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे अहम यह कि इस माध्यम से भारत के नागरिकों को शासन प्रणाली का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, जिसकी मात्रा लोकतंत्र या दूसरे शब्दों में, जनता के राज का सबसे अच्छा पैमाना है। हालांकि शासन में पारदर्शिता लागू करके एक शुरुआत की गई है, लेकिन यह शुरुआत भर है। और जवाबदेही बनती तो और भी कम दिखाई दे रही है। तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है?

स्पष्टतया, सब के लिए प्रथम जरूरत केवल तमाम नागरिकों के बीच अपने अधिकार के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता बनना नहीं है। उस कानून का लाभ क्या जिसका इस्तेमाल न किया जाए, और जो लोग इससे अनजान हैं, वे उपयोग करने से रहे।

अब आगे देखने का समय आ गया है। यह अधिनियम शासन व्यवस्था का एक हिस्सा बन गया है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए, सरकार के अंग के रूप में जनता को पंचायतों, न्यायपालिका, नौकरशाही के जरिये व उन विधानमंडलों के जरिए, जिनके सदस्य इस अधिनियम के स्वामी हैं, स्वयं आगे आकर नेतृत्व करना होगा।

प्रेरणा

जीवन का सत्यबोध : अस्थायी संसार में स्थायी आत्मा की खोज

गांव के किनारे, हरियाली से घिरे खेतों के बीच एक किसान रहता था। उसका जीवन सरल था, पर उसके भीतर ज्ञान का अमृत भरा था। वह दिनभर अपने खेतों में हल चलाता, मिट्टी में अपनी रोटी ढूंढता और रात को ईश्वर का ध्यान करता। गांव के लोग उसे आदर से देखते, क्योंकि उसके जीवन में लोभ नहीं था, केवल श्रम और शांति थी। वह न किसी से ईर्ष्या करता, न किसी का अहित चाहता।

कई वर्षों तक उसके घर से बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। उसकी पत्नी, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ और सौम्य स्वभाव की थी, हर मंदिर में दीप जलाती, हर व्रत करती, बस यही प्रार्थना करती कि उनके जीवन में एक संतान का सुख आ जाए। अंततः एक दिन ईश्वर की कृपा हुई। पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। किसान ने उसका नाम रखा — हारू। हारू के जन्म के बाद किसान का जीवन जैसे बदल गया। वह अपने बेटे को गोद में उठाकर खेतों में ले जाता, उसे मिट्टी से खेलते देखता और मुस्कुराता। मां बेटे को देखकर अपने सारे दुख भूल जाती। उनके छोटे से घर में अब हंसी की गूंज थी, चूल्हे की रोटी अब पहले से भी मीठी लगने लगी थी। गांव के लोग कहते, "किसान का भाग्य खुल गया, अब इसका वंश चलेगा।"

लेकिन जीवन कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होता। जैसे फसलें कभी बाढ़ से बह जाती हैं, वैसे ही सुख के बीच दुख की बयार आ जाती है। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था कि एक युवक हांफता हुआ दौड़ता आया। उसने कहा, "भैया, जल्दी चलो! हारू को हैजा हो गया है।" किसान का चेहरा एक पल को जड़ हो गया। उसने हल छोड़ दिया और पूरे वेग से घर की ओर भागा।

घर पहुंचा तो देखा, उसका बेटा पीड़ा में तड़प रहा था। डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाया गया, जड़ी-बूटियां दी गईं, पर बीमारी ने दया नहीं की। कुछ घंटों बाद हारू ने मां की गोद में अंतिम सांस ली। एक करुण क्रंदन पूरे घर में गूंज उठा। औरतें सिर पीटने लगीं, पड़ोसी रोने लगे, लेकिन किसान शांत बैठा रहा। उसका चेहरा वैसा ही स्थिर था जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो।

जब सब लोग बेटे की देह के पास बैठे रो रहे थे, किसान उठकर बाहर चला गया और फिर अपने खेत की ओर चल पड़ा। शाम ढले वह वापस आया तो उसकी पत्नी आंखें लाल किए बैठी थी। उसने आंसुओं से भरी आवाज़ में कहा, "क्या तुम्हारा हृदय पत्थर का है? हमारा इकलौता बेटा मर गया, और तुम्हारी आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा!"

किसान ने गहरी सांस ली और बहुत शांत स्वर में बोला, "आज जो सत्य मैंने जाना है, वह तुम्हें भी जानना चाहिए।"

पत्नी ने क्रोध और दुख से कांपती आवाज़ में कहा, "कौन सा सत्य? क्या पुत्र की मृत्यु में भी कोई सत्य है?"

किसान बोला, "कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैं एक महान राजा था। मेरे आठ पुत्र थे — सब बलवान, सुंदर और बुद्धिमान। मैं ऐश्वर्य में डूबा था, मेरा दरबार चमक रहा था। अचानक किसी ने मुझे झकझोरा, और मेरी आंख खुल गई। अब सोचो, मैं उन आठ पुत्रों के लिए रोऊं जो स्वप्न में थे, या इस एक हारू के लिए जो इस जागृत स्वप्न में था?"

पत्नी अवाक रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब उनमें दुख की जगह एक गहरी समझ उतर रही थी। किसान ने आगे कहा, "जैसे स्वप्न टूटता है, वैसे ही यह संसार भी एक दिन टूट जाएगा। जब हम सोते हैं तो स्वप्न का संसार सच लगता है, पर आंख खुलते ही सब मिट जाता है। वैसे ही यह जागृति भी एक दूसरा स्वप्न है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है।"

उसने मिट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, "यह मिट्टी बदलती है, ऋतुएं बदलती हैं, देह बदलती है, भाव बदलते हैं — लेकिन जो इन सबका साक्षी है, वह आत्मा न बदलती है, न मिटती है। वह न जन्म लेती है, न मरती है। वही सत्य है, वही ईश्वर है। जब यह समझ आ जाती है, तब किसी के जाने का शोक नहीं रहता, क्योंकि आत्मा कभी जाती ही नहीं — केवल रूप बदलती है।"

पत्नी ने धीरे से अपने आंसू पोंछे। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई गहरा द्वार खुल गया हो। वह पहली बार अपने दुख से ऊपर उठी थी। उसने पति का हाथ पकड़ा और बोली, "तुमने आज मुझे वह दिखाया जो मैं आंखों से नहीं देख पाई थी — जीवन का सत्य।"

किसान मुस्कुराया और बोला, "जीवन का सत्य समझ लेने के बाद मृत्यु भी भय नहीं देती। जब आत्मा को पहचान लो, तब शोक अपने आप मिट जाता है। तब सुख-दुख, हानि-लाभ सब एक समान लगते हैं। तभी मनुष्य वास्तव में जीना शुरू करता है।"

रात उतर आई थी। गांव शांत था। किसान और उसकी पत्नी आंगन में दीपक जलाकर बैठे थे। हवा में शांति थी, और भीतर कहीं आत्मा की अनंत रोशनी चमक रही थी। वे दोनों मौन थे, पर उस मौन में अनंत ज्ञान था — उस सत्य का ज्ञान, जो कभी न जन्म लेता है, न मरता है, बस साक्षी बनकर सब देखता है।

यही है जीवन का सत्यबोध — कि यह संसार एक क्षणिक स्वप्न है, और आत्मा उस स्वप्न का शाश्वत दर्शक।

एक लाख एकल शिक्षक स्कूलों की त्रासदी से त्रस्त शिक्षातंत्र

भारत में आज भी कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे सभी विषय पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के साल 2024-25 के आधिकारिक डेटा के मुताबिक देश के कुल 1,04,125 स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं एवं सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता ही नहीं रहा है बल्कि चिन्ताजनक स्थिति को बयां कर रहा है। ये आंकडे.हमारे शैक्षणिक विकास पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। "शिक्षा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है।" स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य आज भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक कसक बनकर उभरता है। जब शिक्षा की आत्मा घायल होती है तो राष्ट्र का शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता।

शिक्षा मंत्रालय के ये हालिया आंकड़े बताते हैं कि एकल शिक्षक स्कूलों में करीब पौने चौंतीस लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। एक तो हमारे देश में शिक्षा का बजट पहले ही बहुत कम है, फिर उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाना एक भ्रष्टाचार ही है। इसमें दो राय नहीं कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के मूल में हमारे नीति-नियंताओं की अनदेखी ही प्रमुख कारक है। आखिर हम अपने नौनिहालों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आखिर उनके बेहतर भविष्य की हम कैसे उम्मीद करें? जाहिर बात है कि एक शिक्षक सामाजिक विषय, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में माहिर नहीं हो सकता। एक शिक्षक छात्रों की हाजिरी दर्ज करेगा या पढ़ाई कराएगा? एकल शिक्षक स्कूलों का परिदृश्य भारत के विकास की पौल खोलने वाला है। भले ही एकल शिक्षक स्कूलों में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई हो, फिर इतनी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूलों का होना हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी को ही उजागर कर रहा है। यह स्थिति किसी एक आंकड़े की नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की गहरी त्रासदी की तस्वीर है।

कल्पना कीजिए-एक शिक्षक जो प्रशासनिक काम भी करता है, मिड-डे मील की निगरानी भी करता है और साथ में सभी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। क्या वह शिक्षक शिक्षक रह जाता है या व्यवस्था का बोझ उठाने वाला मज़दूर बन जाता है? इन बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, जिनके लिए ज्ञान का एकमात्र द्वार ही थकान, उपेक्षा और तंगहाली से भरा है? यह संकट केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ विषय विशेषज्ञों की कमी, प्रयोगशालाओं की अनुपस्थिति और शिक्षण संसाधनों का अभाव है। नई शिक्षा नीति 2020 समग्र शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब आधारभूत ढाँचा ही अपूर्ण हो तो नीतियाँ केवल दस्तावेज़ बनकर रह जाती हैं। हम 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, पर क्या एकल शिक्षक स्कूलों की यह स्थिति उस दिशा में कोई सार्थक कदम का संकेत है?

यह विडंबना है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, पर उसके बचपन की शिक्षा का यह हाल है। शिक्षा पर सरकारी व्यय जीडीपी का केवल 2.9 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह 5 से 6 प्रतिशत तक है। जब शिक्षा ही निवेश नहीं बनेगी, तो विकास का आधार कहाँ से आएगा? समस्या केवल शिक्षक संख्या की नहीं, बल्कि शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और संसाधनों की भी है। राज्यों में नियुक्ति प्रक्रियाएँ वर्षों तक लटकी रहती हैं, स्थानांतरण नीति अव्यवस्थित है, और जो शिक्षक हैं भी, उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति, डिजिटल शिक्षण, नवाचार और नैतिक मूल्य आधारित शिक्षण के प्रशिक्षण से वंचित रखा गया है। यह स्थिति उस समय और अधिक विडंबनापूर्ण लगती है जब हम हर मंच पर "नया भारत", "विकसित भारत" और "विश्वगुरु भारत" के नारे लगाते हैं। शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखने की आवश्यकता है। रक्षा और स्वास्थ्य की तरह शिक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हो, दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों का समुचित समायोजन किया जाए, तकनीक के माध्यम से डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो और शिक्षकों को केवल वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बल्कि राष्ट्रनिर्माता के रूप में सम्मान मिले। महात्मा गांधी ने कहा था, "यदि हमें भारत को पुनः महान बनाना है, तो शिक्षा को पुनः मानवीय बनाना होगा।" आज शिक्षा केवल परीक्षा और नौकरी तक सीमित हो गई है, जबकि उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण और विवेक जागरण होना चाहिए। यदि 34 लाख बच्चे एकल शिक्षक के भरोसे हैं, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक संवेदनहीनता का प्रमाण है। भारत तभी विकसित होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा-सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में शिक्षित होगा। अन्यथा, एकल शिक्षक की यह पीड़ा आने वाले भारत की मौन त्रासदी बन जाएगी। शिक्षक दीपक की तरह होते हैं, वे स्वयं जलकर समाज को प्रकाश देते हैं। पर जब दीपक ही अकेला रह जाए, तो अंधकार स्वाभाविक है। अब समय है कि हम इस अंधकार को दूर करने का संकल्प लें, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र का भविष्य है और शिक्षक उस भविष्य के निर्माता हैं।

सोचने वाली बात है कि एक स्कूल की सारी कक्षाओं को एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा? छात्र-छात्राएं कैसी और कितनी शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे? शिक्षा का मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो किताबी पढ़ाई कैसी होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह हो, उसके लिए खेलकूल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों एवं योग-व्यायाम जैसी कक्षाओं की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो शिक्षा के साथ चलने वाली इन गतिविधियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निस्संदेह, हम छात्रों के बीमार भविष्य की बुनियाद ही रख रहे हैं और ऐसी बीमार बुनियाद पर खड़ा राष्ट्र कैसे स्वस्थ, सक्षम एवं उन्नत होगा?

अभियान

अंधेरे में उजाले की लौ – धनतेरस पर 'यम दीपक' जलाने का रहस्य

भारत के हर आँगन में दीपावली से पहले जब संध्या ढलती है और आकाश धीरे-धीरे सांझ के रंगों में घुल जाता है, तब घरों के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है, जिसे लोग 'यम दीपक' कहते हैं। यह दीपक केवल मिट्टी और तेल से नहीं बनता, यह बनता है श्रद्धा, आस्था और भय पर विजय की भावना से। यह वह दीपक है जो मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित होता है, ताकि परिवार का कोई भी सदस्य अकाल मृत्यु का शिकार न हो। यह दीपक मनुष्य की सबसे गहरी जिजीविषा का प्रतीक है — अंधकार से जूझते हुए भी प्रकाश की लौ को जलाए रखना।

धनतेरस का दिन इस पवित्र परंपरा की शुरुआत का दिन है। यह वही तिथि है जब भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरि को आयु और स्वास्थ्य के देवता कहा गया है। अतः इस दिन केवल धन नहीं, बल्कि दीर्घायु और आरोग्य की भी कामना की जाती है। इसी कारण इस दिन लोग अपने घर की सफाई करते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, नए

बर्तन लाते हैं और संध्या में दीपक जलाकर अपने घर को उजाले से भर देते हैं। लेकिन इन सब दीपों में सबसे विशेष होता है वह दीप जो घर के बाहर, दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है — वही है 'यम दीपक'।

यम दीपक की कथा बहुत प्राचीन है। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नाम के नगर में हिमक नामक राजा का पुत्र था। जब उसका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कहा कि यह बालक बहुत गुणवान होगा, परंतु इसके विवाह के चौथे दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। राजा और रानी यह सुनकर व्यथित हो गए, परंतु भाग्य को कौन टाल सकता था। समय बीता, बालक युवा हुआ। एक दिन जब उसका विवाह निश्चित हुआ, तब वह कन्या के घर गया और विवाह संपन्न हुआ। जब वह अपनी नववधू के साथ घर लौटा, तो रात का समय था, चारों ओर शांति थी। पर उसकी पत्नी को पहले से यह ज्ञात था कि यह चौथा दिन उसके पति के जीवन का अंतिम दिन है। वह भयभीत नहीं हुई, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ सोचने लगी कि यदि प्रेम में शक्ति है तो वह अपने पति को मृत्यु से बचा लेगी।

उसने चारों ओर दीपक जलाए। आंगन में, कमरे में, द्वार पर, और पति के चारों ओर दीपों की माला बनाकर रख दी। रात का अंधेरा घना हो गया, पर घर में चारों ओर उजाला फैला हुआ था। उसने अपने पति को सुला दिया और स्वयं जागती रही। वह लगातार दीपकों में तेल डालती रही, ताकि कोई भी दीपक बुझ न जाए। वह कथा सुनाती रही, भजन गाती रही, भगवान यमराज का नाम लेती रही। जब यमराज अपने दूतों के साथ वहां आए, तो उन्हें वह स्त्री दिखाई दी जो प्रेम और भक्ति से दमक रही थी। उसके चारों ओर दीपों का प्रकाश ऐसा था मानो अंधकार वहां पहुँच ही न सकता हो। यमराज ने अपने दूतों से कहा, "यह प्रेम की ज्योति है, यहाँ से किसी के प्राण नहीं लिए जा सकते।"

यमराज ने उस स्त्री की भक्ति और पति के प्रति निष्ठा देखकर प्रसन्न होकर कहा, "तुम्हारे पति का जीवन मैं लौटा देता हूँ। आज से जो भी धनतेरस की रात इस प्रकार दीप जलाएगा, मैं उसके परिवार को अकाल मृत्यु से मुक्त रखूँगा।" उसी दिन से यम दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है।

यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का एक गूढ़ सत्य है। यम दीपक हमें सिखाता है कि मृत्यु को हराने का एक ही उपाय है — प्रकाश। जब हम घर के द्वार पर वह दीप जलाते हैं, तो यह केवल यमराज के सम्मान में नहीं होता, यह उस भय पर विजय की घोषणा होती है जो मनुष्य के भीतर सदियों से छिपा है। यह दीप कहता है कि जो जीवन से प्रेम करता है, जो अंधकार से नहीं डरता, वह मृत्यु से भी नहीं डरता।

धनतेरस की रात जब सूरज ढल जाता है और धरती पर गहराता हुआ अंधकार फैलता है, तब लोग एक मिट्टी का दीपक लेते हैं। उसमें सरसों का तेल डालते हैं, सूती बाती लगाते हैं और श्रद्धा से घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा मानी गई है। दीपक के पास काले तिल रखे जाते हैं और प्रार्थना के रूप में यह मंत्र बोला जाता है —

"मृत्युनां दण्डपालाय कालेन सह भारत।
त्रयोदश्यां दीपदानं, अकालमृत्युं हरतु मे॥"

यह मंत्र केवल एक आवाहन नहीं, बल्कि एक आत्मसंवाद है — मृत्यु से कहा जा रहा है, "हे मृत्यु, जब तक मेरे घर में यह दीप जलता रहेगा, तब तक मेरे भीतर का अंधकार मुझ पर अधिकार नहीं करेगा।"

यह दीपक एक प्रतीक है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने भीतर की लौ बुझने नहीं देनी चाहिए। जब बाहर अंधेरा हो, तब भी मनुष्य को अपने भीतर का दीप जलाना चाहिए। यही दीप यम दीपक कहलाता है — जो मृत्यु को भी रोशनी में बदल देता है।

और इस प्रकार हर वर्ष धनतेरस की रात जब असंख्य दीपक जलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो समूचा भारत कह रहा हो — "हम मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि हमारे भीतर प्रकाश की ज्योति जलती है।" यही वह क्षण होता है जब यम भी झुक जाते हैं, क्योंकि प्रेम, आस्था और उजाला उनसे भी बड़ा सत्य है। यही यम दीपक का रहस्य है, यही उसकी अनंत परंपरा।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत महानगर पालिका के सर्टिफाइड ग्रीन बॉण्ड की मुंबई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेल रिंगिंग कर लिस्टिंग कराई

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने इकोलॉजी व इकोनॉमी के बीच उम्दा संतुलन बनाए रखा है
- सूरत शहर तथा महानगर पालिका स्वच्छता एवं ग्रीन मोबिलिटी क्षेत्र में देशभर में आदर्श
- सूरत मनपा के 'म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड इश्यू' में वैश्विक निवेशकों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ी है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को मुंबई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूरत महानगर पालिका के म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड की बेल रिंगिंग कर लिस्टिंग कराई। इस अवसर पर सूरत के महापौर श्री दक्षेश मावाणी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से ग्रीन एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोगों को भागीदार बनाया गया है। सूरत महानगर पालिका के ग्रीन बॉण्ड को 8 गुना सब्सक्रिप्शन दर्शाता है कि निवेशकों ने ग्रीन बॉण्ड में निवेश करने में असाधारण उत्साह दिखाया है। श्री पटेल ने कहा कि सूरत मनपा के दीर्घदृष्टि से युक्त आयोजन सूरत का विकास अधिक तेज बनाएंगे। वर्ष 2070 तक प्रधानमंत्री के नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकार ने ग्रीन ग्रोथ तथा ग्रीन मोबिलिटी पर विशेष बल दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने इकोलॉजी तथा इकोनॉमी के बीच उम्दा संतुलन बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' के संदेश के साथ सदस्य देशों ने भी प्रधानमंत्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प किया है। यह संकल्प पूर्ण करने के लिए गुजरात ने 'विकसित गुजरात@2047' के रोडमैप सहित अनेक विकासोन्मुखी आयाम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री सदैव जन भागीदारी के आग्रही रहे हैं। 'सरकारी पद्धति को प्रभावशाली बनाने' के ध्येय के साथ राज्य व केन्द्र सरकार के जन हितकारी प्रयास रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सूरत शहर तथा महानगर पालिका स्वच्छता तथा ग्रीन मोबिलिटी क्षेत्र में देशभर में आदर्श बने हैं। उन्होंने इसके लिए सूरत मनपा के शासक-प्रशासकों को अभिनंदन दिया। इस संदर्भ में श्री पटेल ने आगे कहा कि देश में सबसे पहली बार इंटरनेशनल ग्रीन सर्टिफिकेशन के साथ म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड इश्यू के जरिये जारी किए गए हैं। ऐसे में सूरत मनपा के म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड इश्यू में वैश्विक निवेशकों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ी है। मनपा ने विकास के उत्तम आयोजन के साथ जन भागीदारी को जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि ग्रीन पॉलिसी फाइनेंसिंग ग्रीन ग्रोथ का उत्तम उदाहरण बनेगा। श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह पहल शहर के विकास के लिए न केवल वित्तीय रूप से लाभदायी सिद्ध होगी, अपितु पर्यावरणीय स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि सूरत मनपा की यह आयोजन अब अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणादायी बनेगा। इस अवसर पर महापौर श्री दक्षेश मावाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ अनिवार्य है।

सूरत मिनी भारत है। सभी ने सूरत के विकास में सहयोग दिया है। सूरत शहर को अब तक लगभग 14 विभिन्न पुरस्कार मिले हैं। सूरत को ग्रीन एनर्जी के साथ विश्व की बेस्ट सिटी बनाना चाहते हैं।

सूरत मनपा द्वारा 200 करोड़ रुपए के लिस्टेड, टैक्सेबल, रिडीमेबल, सेक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल म्युनिसिपल बॉण्ड डिबेंचर के रूप में जारी किए गए थे। ये ग्रीन बॉण्ड 6 अक्टूबर 2025 को खुले थे और 9 अक्टूबर 2025 को बंद हुए थे। इस अवधि के दौरान सूरत मनपा के ग्रीन बॉण्ड 200 करोड़ रुपए की डिमांड के समक्ष 800 करोड़ रुपए तक छलके हैं, जिसके चलते ग्रीन शू सिस्टम से बॉण्ड का आवंटन होगा। रीटेल सेक्टर में मनपा द्वारा कुल बॉण्ड का 15 प्रतिशत के हिसाब से 30 करोड़ रुपए के आवंटन का ऑफर आमंत्रित किया गया था।

सूरत मनपा आयुक्त श्री शालिनी अग्रवाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि देश में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय सर्टिफाइड ग्रीन बॉण्ड सूरत मनपा लाई है। इसके माध्यम से एकत्र होने वाली राशि पर्यावरण का जतन करने के साथ ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट के रिसोर्स पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जल संचय से जुड़े प्रोजेक्ट और ग्रीन परिवहन की दिशा में साकार होन वाले प्रोजेक्ट में ग्रीन बॉण्ड महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक श्री आशिष चौहाण ने गुजरात सरकार तथा सूरत महानगर पालिका को ग्रीन बॉण्ड की लिस्टिंग पर बधाई दी। इस अवसर पर भारत सरकार के सुजीत सिंह, अग्रणी श्री एन. के. मेहता, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सूरत मनपा के अधिकारी-पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भावनगर मंडल के बोटाद स्टेशन पर "अमृत संवाद" कार्यक्रम का आयोजन

(जीएनएस)। "स्पेशल कैम्पेन 5.0" के अंतर्गत पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा 15 अक्टूबर, 2025 को बोटाद स्टेशन पर "अमृत संवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर यात्रियों के साथ संवाद स्थापित कर "अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS)" के तहत बोटाद स्टेशन पर किए गए विकास कार्यों की जानकारी साझा की गई। यात्रियों को बताया गया कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेल की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर के स्टेशनों का चरणबद्ध तरीके से उनका विकास एवं आधुनिकीकरण कर उन्हें अधिक सुविधाजनक, स्वच्छ और आधुनिक बनाना है।

योजना के अंतर्गत सतत विकास, डिजिटल सूचना प्रणाली, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन कार्यों में जनभागीदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बोटाद स्टेशन पर 9.21 करोड़ की लागत से विभिन्न यात्री सुविधाएँ विकसित की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

- प्लेटफार्मों का पुनःसतहीकरण

- प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 4 पर नए प्रतीक्षालयों एवं शौचालय ब्लॉकों का निर्माण
- दिव्यांग अनुकूल सुविधाएँ
- नए प्रवेश एवं निकास द्वार
- सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग का विकास
- स्टेशन भवन का फसाड सुधार, प्रकाश व्यवस्था एवं लैंडस्केपिंग कार्य

साथ ही 28.46 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें लिफ्ट सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य को 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे आवागमन और यात्री सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा।

इन प्रयासों के माध्यम से भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक एवं यात्री-मित्र वातावरण प्रदान करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। बोटाद स्टेशन को एक आकर्षक और आधुनिक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य गति पर है। कार्यक्रम के दौरान यात्रियों से उनके सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ भी आमंत्रित की गईं। यात्रियों ने रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा कुछ उपयोगी सुझाव भी प्रस्तुत किए, जिन पर रेलवे प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री अनुभव सक्सेना ने वडोदरा मंडल पर जनसंपर्क अधिकारी का कार्यभार संभाला

(जीएनएस)। श्री अनुभव सक्सेना ने पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यभार संभाल लिया है।

श्री अनुभव वडोदरा के जनसंपर्क अधिकारी पद पर आने से पूर्व पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय, चर्चगेट, मुंबई में जनसंपर्क अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) के पद पर कार्यरत थे।

लखनऊ विश्वविद्यालय से जनसंपर्क एवं मास कम्युनिकेशन में परास्नातक श्री अनुभव को प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य का गहन अनुभव प्राप्त है। पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय, चर्चगेट में जनसंपर्क अधिकारी पद पर रहते हुए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बेहतर संवाद के साथ साथ सोशल मीडिया एवं डिजिटल मीडिया में पश्चिम रेलवे के लिए कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की एवं WR समाचार एवं WR पॉडकास्ट जैसे इनोवेटिव पहल में अपना अहम योगदान दिया है।

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने राजस्थान के 65 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से जुड़े प्रमुख विभिन्न कार्यों का राष्ट्र को समर्पण किया

(जीएनएस)। रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने आज खातीपुरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने तथा आधुनिक और कुशल रेल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। ये पहल राज्य के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को रूपांतरित करने और यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हैं।

श्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के 65 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें रामसर, सिवानी, लूनी, पृथ्वीराज पुर और भगत की कोठी जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन

सुधारों में प्रतीक्षालयों का आधुनिकीकरण, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, उन्नत स्वच्छता सुविधाएँ, बैठने की सुविधाएँ, स्पष्ट साइनबोर्ड और दिव्यांगजन के अनुकूल इंतजाम शामिल हैं, जिससे स्टेशन और अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और यात्रियों के अनुकूल बन गए है।

साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने जयपुर–आसारवा एक्सप्रेस की सभी एसी श्रेणियों में मुद्रित कंबल कवर (printed blanket covers) की नई व्यवस्था शुरू की, जिससे यात्रा में स्वच्छता, एकरूपता और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित होगा।

कार्यक्रम के दौरान माननीय केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे का विकास कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई प्रकार की ट्रेनों की शुरुआत, नए स्टेशनों का निर्माण, नई रेल लाइनें, विद्युतीकरण कार्यों की पूर्णता और आधुनिक रखरखाव डिपो का निर्माण जारी है। उन्होंने कहा कि इन सबके साथ ही रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना है।

केंद्रीय बजट 2025–26 में राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 9,960 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश में 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से इस वर्ष 8 स्टेशनों का लोकार्पण हो चुका है। राज्य में आज 12 वंदे भारत सेवाएं संचालित हो रही हैं, जो प्रमुख मार्गों पर तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान कर रही हैं।

ये योजनाएँ राजस्थान में आधुनिक, कुशल और यात्री-केंद्रित बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

दीवाली एवं छठ पर्व के दौरान अधिकृत यात्रियों की सुविधा हेतु अहमदाबाद एवं साबरमती स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से स्थगित

(जीएनएस)। दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 से 27 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगी यह व्यवस्था

आगामी दीवाली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की भारी आवाजाही को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद एवं साबरमती रेलवे स्टेशनों पर भीड़-प्रबंधन एवं यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

यह व्यवस्था दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 से 27 अक्टूबर, 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री सभी माध्यमों से अस्थायी रूप से बंद रहेगी।

यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु एक अस्थायी एवं नियोजित कदम है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की यात्रा अनुभव को सुरक्षित एवं सुखद बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

रेलवे प्रशासन की अपील है कि यात्रीगण एवं नागरिक इस अवधि में अनावश्यक भीड़ से बचें तथा स्टेशन परिसर में केवल यात्रा संबंधी कार्यों के लिए ही उपस्थित हों, ताकि सभी के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज द्वारा सन्तोष कुमार झा 'राजभाषा सम्मान' से अलंकृत

(जीएनएस)। मुंबई, 16 अक्टूबर। विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अधिवेशन के दूसरे दिन नैनी, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में स्थित जगतपिता ब्रह्मदेव धर्मशाला, देवरख में 'हिन्दी संगोष्ठी' एवं 'सम्मान समारोह' आयोजित किया गया, जिसमें कोंकण रेलवे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सुप्रसिध्द कवि सन्तोष कुमार झा को उनके नेतृत्व में किये जा रहे उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु "राजभाषा सम्मान– 2024" से गौरवान्वित किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त डॉ. सुरेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि संस्कृत और हिन्दी एक ही सांस्कृतिक परंपरा की

भाषाएँ हैं। अंग्रेज़ी जानना आवश्यक है, पर हिन्दी की कीमत पर नहीं। विशिष्ट अतिथि डॉ. एन. बी. सिंह 'हरियाली गुरु' रहे। इस अवसर पर अनेक साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। उसी क्रम में, कोंकण रेलवे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा प्रसिध्द कवि श्री सन्तोष कुमार झा को उनके नेतृत्व में किये जा रहे उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु "राजभाषा सम्मान– 2024" से गौरवान्वित किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री झा के चार काव्य संग्रह 'उन्मुक्त', 'सूरज का वारिस', 'फूल, कलम और बंदूक' तथा 'स्याही का सिपाही' प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य सम्मानित साहित्यकारों में डॉ. वंदना अग्निहोत्री, डॉ. सीमा वर्मा, डॉ. विजयलक्ष्मी, रजनी प्रभा, फरहत, राणा प्रताप सहित अनेक विद्वान शामिल रहे। मंच संचालन डॉ. सीमा वर्मा एवं रश्मि चौबे ने किया तथा डॉ. गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी ने आभार व्यक्त किया।

पश्चिम रेलवे चलायेगी अहमदाबाद–शेखपुरा के बीच स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा आगमी दिवाली त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद-शेखपुरा के बीच स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09463/09464 अहमदाबाद-शेखपुरा-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (04 फेरे)

ट्रेन संख्या 09463 अहमदाबाद-शेखपुरा स्पेशल अहमदाबाद से 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) और 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार) को दोपहर 15:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 04:00 बजे शेखपुरा पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या

09464 शेखपुरा-अहमदाबाद स्पेशल शेखपुरा से 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार) और 25 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को सुबह 06:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा दूसरे दिन साँय 20:00 बजे अहमदाबाद पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन नदियाद, आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मकसी, संत हिरदारम नगर, बिना, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिक्की, मिर्ज़ापुर, पं. दिन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ, सासाराम, डेहरी ऑनसोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, तिलैया, नवादा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09463 की बुकिंग 17 अक्टूबर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जोधपुर,के बीच चलाएगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दिवाली एवं छठ पूजा के त्योहारी सीज़न के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं जोधपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 04826/04825 बांद्रा टर्मिनस – जोधपुर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [04 फेरे]

ट्रेन संख्या 04826 बांद्रा टर्मिनस – जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस से 21:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21:45 बजे जोधपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, 2025 को चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04825 जोधपुर – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक बुधवार को जोधपुर से 17:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 18:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, 2025 को चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, फुलेरा, नवा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, रेन, मेड़ता रोड और गोटन स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04826 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर 18 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

आंबलियासन–विजापुर रेलखंड का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण, संरक्षा निरीक्षण जारी

- **42.32 किमी लंबा खंड अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित,**
- **16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को हो रहा है संरक्षा निरीक्षण**

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन–विजापुर रेलखंड (42.32 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह रेलखंड वर्ष 1902 में मीटर गेज लाइन के रूप में प्रारंभ हुआ था और अब इसका ब्रॉड गेज में परिवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है। अब यह खंड यात्रियों के लिए आधुनिक एवं सुरक्षित परिचालन हेतु तैयार है। इस खंड का संरक्षा निरीक्षण (Safety Inspection) रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम रेलवे श्री ई. श्रीनिवास द्वारा 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को किया जा रहा है।

पिछले दो महीनों में रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) द्वारा लगभग 100 किमी खंडों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनमें हाल ही में सम्पन्न हिम्मतनगर–खेडब्रह्मा रेलखंड (54.83 किमी) का CRS निरीक्षण भी शामिल है। साथ ही, विजापुर–आदराज मोती रेलखंड (39.85 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य भी शीघ्र पूर्ण होने की दिशा में है, जिसका संरक्षा निरीक्षण आगामी दिनों में किया जाएगा।

दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को निरीक्षण के प्रथम दिवस पर रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा आंबलियासन से कूकरवाड़ा तक कुल 26.61 किलोमीटर लंबाई के खंड का मोटर ट्रॉली के माध्यम से विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंबलियासन स्टेशन से निरीक्षण प्रारम्भ किया गया तथा सिग्नल एवं इंटरलॉकिंग पैनल की कार्यप्रणाली की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, RUB नंबर 98A एवं 79B पर ऊँचाई माप (Height Gauge) एवं जल निकासी (Drainage Arrangement) की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया।

आगे लांघंज स्टेशन तथा गोझारिया स्टेशन का भी संरचनात्मक एवं सिग्नलिंग निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही लेवल क्रॉसिंग नंबर 69, 77, 78 एवं 88, मेजर ब्रिज नंबर 85A एवं 97 का निरीक्षण किया गया। सभी स्थलों पर मोटर ट्रॉली द्वारा ट्रैक संरचना, पुल, सिग्नलिंग व्यवस्था एवं सुरक्षा उपायों की गहन समीक्षा की गई।

निरीक्षण टीम में श्री ई. श्रीनिवास, रेल सुरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम रेलवे, श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण एवं ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

परियोजना के अंतर्गत इस खंड में कुल 02 मेजर ब्रिज, 51 माइनर ब्रिज तथा 45 नए रोड अंडर ब्रिज (RUBs) का निर्माण किया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलवे लाइन को लेवल क्रॉसिंग के समीप फेंसिंग द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इस खंड पर कुल 04 लेवल क्रॉसिंग्स हैं।

ब्रॉड गेज ट्रैक में 60 किलोग्राम के नए

रेल पैनल बिछाए गए हैं। आंबलियासन एवं विजापुर स्टेशनों को स्टैंडर्ड-II इंटरलॉकिंग सिस्टम और मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग (MACLS) से सुसज्जित किया गया है, जिससे ट्रेनों के संचालन की सुरक्षा एवं दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

यह नया ब्रॉड गेज खंड देश के प्रमुख रेलवे नेटवर्क से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रियों को अधिक तेज़, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना से उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जिससे यात्रा समय में कमी, व्यापार एवं कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था में सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।

इस खंड के चालू होने से विजापुर क्षेत्र के प्रसिद्ध गेहूँ, आलू एवं तेल उत्पादों की आपूर्ति देशभर में अधिक सुगमता से हो सकेगी, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी।

संरक्षा निरीक्षण के अंतिम दिन, 17 अक्टूबर 2025 को इंजन स्पीड ट्रायल 120 किमी/घंटा की गति से किया जाएगा, जिसके पश्चात इस खंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किए जाने की दिशा में आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी।

पश्चिम रेलवे की यह परियोजना यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

प्रतापनगर से जयनगर के लिए रविवार को अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दिवाली एवं छठ पूजा के त्योहारी सीज़न के दौरान उनकी यात्रा माँग को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतापनगर-जयनगर स्टेशन के बीच विशेष किराए पर अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाईगी।

1. ट्रेन संख्या 09151/09152 प्रतापनगर-जयनगर अनारक्षित स्पेशल (साप्ताहिक) [04 फेरे]

ट्रेन संख्या 09151 प्रतापनगर - जयनगर स्पेशल रविवार, 19 और 26 अक्टूबर 2025 को 16:35 बजे प्रतापनगर से प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 10:00 बजे जयनगर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09152 जयनगर - प्रतापनगर स्पेशल मंगलवार, 21 और 28 अक्टूबर, 2025 को 14:00 बजे जयनगर से प्रस्थान करेगी और गुरुवार को 05:30 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, कटनी मुरवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छेवकी, मिर्ज़ापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर रेलवे मंडल के धोला जंक्शन रेलवे कॉलोनी में "सांस्कृतिक संध्या" कार्यक्रम का सफल आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारी हित निधि के सौजन्य से दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 को धोला जंक्शन रेलवे कॉलोनी में "सांस्कृतिक संध्या" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए एक सकारात्मक मंच प्रदान करना था। यह आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से शाम 5:00 बजे से आरंभ हुआ।

कार्यक्रम में रेलवे कॉलोनी के बच्चों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए संगीत एवं नृत्य की शानदार प्रस्तुतियाँ दीं। दर्शकों ने पूरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन जी ने रेलवे में चल रही विविध कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया तथा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया।

कार्यक्रम के दौरान सहायक कार्मिक अधिकारी श्री संतोष कुमार वर्मा जी ने कॉलोनी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए प्रेरित किया तथा "बेस्ट कैप्ट रेलवे क्वार्टर अवार्ड" के रूप में एक नवाचार प्रस्तुत किया। इस पहल के तहत ESM श्री अमोल डोंगरे को वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के करकमलों से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धोला शाखा के शाखा प्रबंधक श्री अजीत कुमार गुप्ता ने एसबीआई रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट के लाभों की जानकारी दी।

इस अवसर पर सहायक मंडल अभियंता श्री विजेंद्र सिंह एवं पश्चिम रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव ने भी कर्मचारियों को प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान किया। पूरे कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री शैलेश परमार (सचिव, कर्मचारी हित निधि एवं कल्याण निरीक्षक) तथा कल्याण निरीक्षकों की टीम का विशेष योगदान रहा, जिनकी मेहनत से "सांस्कृतिक संध्या" कार्यक्रम सफलता के साथ संपन्न हुआ।

सुप्रीम कोर्ट में वकील द्वारा CJI पर जूता फेंकने की घटना से मचा बवाल, अटॉर्नी जनरल ने दी अवमानना कार्रवाई की मंजूरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत में अभूतपूर्व घटना के बाद गुरुवार को नया मोड़ तब आया जब अटॉर्नी जनरल ने उस वकील के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की अनुमति दे दी, जिसने 6 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंका था। इस घटना ने न्यायपालिका की गरिमा और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने इस घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि यह सिर्फ एक अदालत की नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसका "महिमा मंडन" किया जा रहा है, जिससे आम जनता में न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है।

हालांकि, इस दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने एक बेहद सधा हुआ और संयमित रुख अपनाया। उन्होंने कहा, "जब अदालत के सामने पहले से ही हजारों जरूरी मामले लंबित हैं, तो क्या हमें इस मुद्दे पर कीमती समय गंवाना चाहिए?" बेंच ने जोड़ा कि इस घटना को खुद CJI ने "एक गैर-जिम्मेदार नागरिक का कृत्य" मानते हुए अनदेखा कर दिया है, इसलिए इसे और बड़ा बनाना शायद उचित नहीं होगा।

विकास सिंह ने कोर्ट से सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में "जॉन डो" आदेश (यानी किसी विशेष व्यक्ति को नामित किए बिना सभी के खिलाफ लागू रोक) पारित किया जा सकता है।

इस पर जस्टिस बागची ने कहा, "ऐसा कोई एकमुश्त आदेश और विवाद को जन्म दे सकता है। न्यायाधीशों को ऐसे हमलों से संयम और गरिमा के साथ निपटना चाहिए। हमारा सम्मान इस बात से तय होता है कि हम खुद को कैसे संभालते हैं।"

बेंच ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका संयम और नैतिक बल है, न कि प्रतिशोध। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "अगर हम इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे, तो यह कई सप्ताह तक चर्चा में रहेगा, और शायद यही वह चाहता भी है।"

CJI गवई ने इस घटना के तुरंत बाद ही कहा था, "यह किसी असंतुष्ट और गैर-जिम्मेदार व्यक्ति का आचरण है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा पर कोई असर नहीं पड़ता।" उन्होंने अदालत की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने का निर्देश दिया था। अब अटॉर्नी जनरल द्वारा दी गई अनुमति के बाद वकील पर अवमानना का औपचारिक केस दर्ज किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की हरकत नहीं है, बल्कि न्यायिक गरिमा और अनुशासन की परीक्षा भी है — और आने वाले समय में यह तय करेगा कि अदालतें ऐसे अनुचित आचरण के प्रति कितनी कठोर या सहनशील रहती हैं।

भारत की वायुसेना ने चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना का दर्जा हासिल किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए चीन को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट (WDMMA) की ताजा रैंकिंग में अमेरिका सबसे ताकतवर वायुसेना के तौर पर पहले स्थान पर है, उसके बाद रूस, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे स्थान पर चीन की वायुसेना है। इस रैंकिंग में केवल विमानों की संख्या को ही नहीं देखा गया, बल्कि आक्रमण और रक्षा क्षमता, सैन्य सहायता, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और रणनीतिक संतुलन जैसे कई पैमानों को ध्यान में रखते हुए गणना की गई है। अमेरिकी वायुसेना का टूवैल रेटिंग (TVR) 242.9 है, रूस की 114.2, भारत की 69.4 और चीन की 63.8 है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी गुणवत्ता और संतुलित रणनीति के दम पर चीन को पीछे छोड़ दिया है।

भारतीय वायुसेना के पास कुल 1,716 विमान हैं, जबकि चीन के पास 3,733 विमान हैं। हालांकि संख्या में भारत कम है, लेकिन इसके बेड़े की संरचना बेहद संतुलित और प्रभावशाली है। भारतीय वायुसेना के कुल विमानों में 31.6 प्रतिशत लड़ाकू विमान, 29 प्रतिशत हेलीकॉप्टर और 21.8 प्रतिशत प्रशिक्षक विमान शामिल हैं। इसके विपरीत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) में 52.9 प्रतिशत लड़ाकू विमान और 28.4 प्रतिशत प्रशिक्षक विमान हैं, जबकि हेलीकॉप्टर और अन्य सहायक विमान कम हैं। यह संतुलन भारत को न केवल लड़ाकू क्षमता देता है, बल्कि आपातकालीन संचालन और रसद प्रबंधन में भी मदद करता है।

वायुसेना के बेड़े में कई आधुनिक और रणनीतिक महत्व के विमान शामिल हैं। फ्रांस में निर्मित राफेल और मिराज 2000, रूस के सुखोई 30 और मिग-29, तथा स्वदेशी विकसित हल्का लड़ाकू विमान तेजस इस बेड़े का हिस्सा हैं। हाल ही में मिग-21 विमानों को रिटायर कर दिया गया है, जिससे बेड़े में आधुनिक तकनीक और लड़ाकू क्षमता में वृद्धि हुई है। भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 600 से अधिक नए लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने में भी तेजी लाई जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस सफलता का मुख्य कारण सिर्फ विमानों की संख्या नहीं, बल्कि उनके आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, रणनीतिक संतुलन, मिशन क्षमता और आधुनिकीकरण है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी वास्तविक युद्धक कार्रवाइयों ने भी भारतीय वायुसेना की वैश्विक रैंकिंग में मजबूती को स्पष्ट किया है। भारत की यह उपलब्धि न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्ति संतुलन को भी संकेत देती है कि भारत आकाश में अपनी उपस्थिति को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सक्षम है।

आने वाले वर्षों में नए लड़ाकू विमानों के शामिल होने और तकनीकी आधुनिकीकरण से भारतीय वायुसेना अपनी ताकत और दायरे को और बढ़ाएगी। यह रैंकिंग यह दिखाती है कि भारतीय वायुसेना ने कम समय में अपनी क्षमता को संख्या और गुणवत्ता दोनों के दृष्टिकोण से मजबूत कर लिया है। इस उपलब्धि से भारत न केवल अपनी हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक ताकत और प्रभाव को भी बढ़ा रहा है।

अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर नक्सल मुक्तः अमित शाह ने कहा—'हिंसा की अंतिम सांसें'

(जीएनएस)। बस्तर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। उन्होंने इस उपलब्धि की जानकारी स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर साझा की और इसे नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक जीत करार दिया। शाह ने लिखा कि वे इलाकों को कभी आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता था, पर आज वहीं क्षेत्र नक्सली हिंसा से मुक्त कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि यह सरकार और सुरक्षा बलों की उत्कृष्ट साझेदारी, लगातार कार्रवाई और लोक-हितकारी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

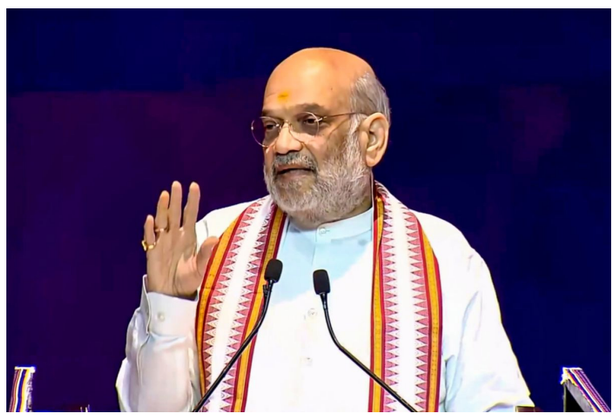

अमित शाह ने अपने संदेश में यह भी बताया कि हाल के दो दिनों में 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है — इनमें से छत्तीसगढ़ में 170 और महाराष्ट्र में 61 नक्सली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कल राज्य में 27 नक्सली हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर चुके थे। शाह ने यह आंकड़े पेश करते हुए यह भी उल्लेख किया कि जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से अब तक कुल 2,100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1,785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने इन उपलब्धियों को 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के संकल्प के हिस्से के तौर पर पेश किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है — जो बंदूकें छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहें उनका स्वागत है, जबकि जो हथियार उठाए रहेंगे उन्हें सुरक्षा बलों की निर्णायक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शाह ने बार-बार यह अपील दोहराई कि जो भी नक्सलवाद की राह पर हैं वे अपने हथियार डालकर संविधान में विश्वास करें और लोकतंत्र का हिस्सा बनें। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के अनुसार, अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर की गहन सैन्य तथा पुलिसीय कार्रवाइयों के साथ-साथ क्षेत्र में सुधरे संभावनात्मक विकास कार्यक्रमों, जन कल्याण पहलों और सामरिक निवास एवं लोक संवाद के कारण नक्सलियों के सफेद झंडा उठाने का क्रम तेज हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में किए गए पुनर्वास, हथियार समर्पण योजनाएँ, आर्थिक अवसर और स्थानीय सुरक्षा गारंटी जैसे कदमों ने भगोड़े कर देने की बजाय लौटने के लिए साफ रास्ता दिखाया। सुरक्षा तंत्र ने पिछले सप्ताह शेव-अप ऑपरेशन, खुफिया नेटवर्क सुख्याने और नक्सलियों के सहयोगी ढांचे पर सख्त कार्रवाई जैसे कई अभियान चलाए, जिनके नतीजे स्वरूप बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण और हथियार संपोषण देखने को मिला।

विशेषज्ञों का कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ यह जीत केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई का परिणाम नहीं है; इस सफलता के पीछे पंचायत-स्तर पर बढ़ा प्रशासनिक जुड़ाव, शिक्षा और स्वास्थ्य के विस्तार, और विकास योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन भी अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि कुछ परिदृश्यों में यह भी सामने आया कि नक्सली गिरोहों के भीतर आई फूट और नेतृत्व के कमजोर होने से भी कई स्थानीय लड़ाके हथियार डालकर सुरक्षित मार्ग तलाशने पर मजबूर हुए। अधिकारियों ने यह भी माना कि अब चूंकि कुछ हिस्सों में शांति आई है, इसलिए वहां विकासात्मक गतिविधियों और पुनर्निर्माण कार्यों का दायरा तेज किया जाएगा ताकि मुख्यधारा में लौटे लोगों को रोज़गार और सम्मानजनक जीवन मिल सके।

राजनीतिक स्तर पर इस घोषणा को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए बड़ा सियासी और प्रशासनिक हासिल माना जा रहा है। अमित शाह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे आंतरिक सुरक्षा और विकासात्मक अभियान की सफलता बताया और कहा कि यह बताता है कि आतंकवाद व उग्रवाद को मिटाने की दिशा में देश दृढ़ संकल्पित है। विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने भी कुछ हद तक इस उपलब्धि की स्वीकार्यता जताई, पर कुछ समूहों ने यह सवाल उठाया कि आत्मसमर्पण प्रक्रिया के साथ न्यायिक और मानवाधिकार संबंधी संरक्षणों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। उनके अनुसार, मुख्यधारा में लौटे लोगों की सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास योजना, शांति स्थापन के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा और भूमि-स्वामित्व जैसे संवेदनशील मुद्दों का पारदर्शी तरीके से निपटान बेहद आवश्यक होगा।

सुरक्षा सूत्रों ने संकेत दिया कि अब दक्षिण बस्तर नक्सलवाद के अंतिम बड़े गढ़ के रूप में शेष है और वहां भी सशक्त अभियान चलाकर शून्य सहिष्णुता नीति के तहत नक्सलियों को खत्म करने की योजना है। अमित शाह ने अपने पोस्ट में स्पष्ट चेतावनी दी कि अभी भी हथियार धारण कर रखे हुए लोगों के लिए विकल्प है — आत्मसमर्पण और मुख्यधारा में लौटना; अन्यथा उन्हें सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करना होगा।

इस बड़ी घोषणा के बाद स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर क्षेत्र में शांति बहाली, पुनर्वास के अलग-अलग मॉडलों और दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में केंद्र और राज्य सरकार की टीमें उन जिलों में जाकर विस्तृत पुनर्वास, सुरक्षा गारंटी और विकास परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नक्सलवाद की वापसी न हो और स्थायी शांति कायम रहे। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर के नक्सल मुक्त होने की यह कहानी, चाहे कई मायनों में उपलब्धि हो, पर इसके सफल और स्थायी क्रियान्वयन के लिए शासन-प्रशासन, स्थानीय समुदाय और सुरक्षा तंत्र को मिलकर काम करना होगा। केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सामाजिक समावेशन के ठोस कदम ही इस जीत को लंबे समय तक कायम रख सकेंगे — यही चुनौती अब नए सिरे से सामने खड़ी है।

पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 13,430 करोड़ की सौगात, बोले– डबल इंजन सरकार से राज्य में दिख रहा विकास का नया युग

(जीएनएस)। कुर्नूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जन सेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण भी मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि यह अवसर आंध्र प्रदेश के विकास यात्रा का नया अध्याय है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर 'विकसित भारत' के सपने को साकार कर रहे हैं।

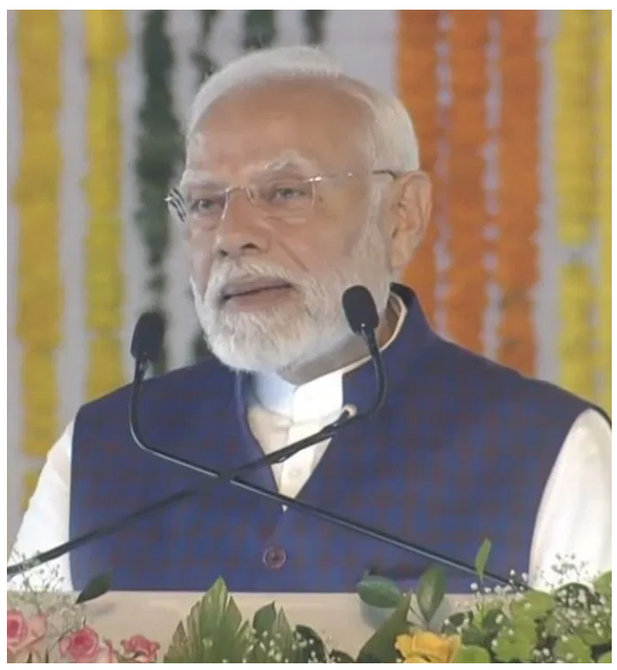

कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने नांदयाल में प्रसिद्ध श्रीशैलम के भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे शिवाजी स्फूर्ति केंद्र पहुंचे और वहां भी विधिवत पूजा की। मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने राज्य और देश की समृद्धि की कामना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश को अब वह नेतृत्व मिल गया है जिसकी उसे वर्षों से आवश्यकता थी। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को "विजनरी लीडर" बताते हुए कहा कि राज्य में अब स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रशासन और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, तो विकास की गति दोगुनी हो जाती है।

प्रधानमंत्री ने कुर्नूल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "आज आंध्र प्रदेश के लोगों को रोजगार, निवेश और विकास की दिशा में ठोस कदमों का लाभ मिलेगा। ये परियोजनाएं सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं हैं, बल्कि नए आंध्र प्रदेश की नींव हैं।"

मोदी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें कुर्नूल-3 पूलिंग स्टेशन पर 2,880 करोड़ की ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना, 4,920 करोड़ रुपये की लागत से ओरवकल और कोप्परथी औद्योगिक क्षेत्र, तथा 1,200 करोड़ की लागत वाली रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में लगभग एक लाख नए रोजगार सृजित होंगे और लगभग 21,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गेल इंडिया की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह गैस पाइपलाइन पूर्वी भारत के ऊर्जा ग्रिड को मजबूत करेगी और औद्योगिक क्षेत्र को नई शक्ति देगी। राजमार्ग और परिवहन क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने 1,140 करोड़ रुपये की छह सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पिलेरु-कलुर सड़क खंड का चार लेन विस्तार, कडप्पा-नेल्लोर सीमा से सीएस पुरम तक चौड़ीकरण, और सब्बावरम से शीलानगर तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि विशाखापत्तनम और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी।

रेल क्षेत्र में भी आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगातें मिलीं। मोदी ने कोट्टावलसा से विजयनगरम तक चौथी रेलवे लाइन, पेंडुर्ती और सिंहाचलम के बीच रेल फ्लाईओवर, कोट्टावलसा-बोड्डावरम सेक्शन और शिमिलिगुडा-गोरपुर सेक्शन के दोहरीकरण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही गुडिवाड़ा-नुजेला रेल ओवर ब्रिज (ROB) का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल यात्री सुविधाओं को बढ़ाएंगी, बल्कि माल परिवहन की क्षमता भी दोगुनी करेंगी।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, समुद्री तट और कृषि क्षमता इसे देश का निवेश केंद्र बना सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि "आज भारत में हर राज्य प्रतिस्पर्धा कर रहा है, और आंध्र प्रदेश इस दौड़ में अग्रणी बनने की क्षमता रखता है।" प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा, "अब आंध्र प्रदेश में विकास का चक्र रुकने वाला नहीं है। जब नायडू जैसे अनुभवी नेता और केंद्र सरकार एक दिशा में काम करते हैं, तो परिणाम निश्चित रूप से ऐतिहासिक होते हैं। यह डबल इंजन सरकार की ताकत है।" जनसभा के अंत में लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन "जय श्रीशैलम" और "भारत माता की जय" के नारों से किया। मोदी ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जल्द ही राज्य में नई परियोजनाओं की घोषणा के साथ फिर लौटेंगे।

FSSAI ने खाद्य उत्पादों में 'ORS' शब्द पर लगाया बैन, हैदराबाद की महिला डॉक्टर की 8 साल की मेहनत रंग लाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। हैदराबाद की महिला डॉक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने पिछले आठ सालों से लगातार लड़ाई लड़कर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को यह सुनिश्चित करने पर मजबूर किया कि किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के नाम, ब्रांड या लेबल में 'ORS' शब्द का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। इस आदेश का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले उत्पादों को बाजार से दूर करना और उन्हें यह स्पष्ट संदेश देना है कि केवल मेडिकल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) ही सही ORS है।

FSSAI ने हाल ही में अपने नए आदेश में स्पष्ट किया कि अब कोई भी खाद्य उत्पाद — चाहे वह फ्रूट-बेस्ड ड्रिंक, रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेज या अन्य पेय पदार्थ हो — 'ORS' शब्द का इस्तेमाल अपने नाम, ब्रांड या पैकेजिंग पर नहीं कर सकता। पहले के आदेशों (14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024) में कुछ कंपनियों को विशेष शर्तों के तहत छूट दी गई थी, लेकिन अब यह सभी छूट समाप्त हो गई हैं। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि अब किसी भी उत्पाद के पैकेज या विज्ञापन में यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी प्रिफिक्स या सफिक्स के रूप में क्यों न हो।

FSSAI ने अपने आदेश में कहा कि इस शब्द का गलत उपयोग उपभोक्ताओं को गुमराह करता है और उन्हें यह भ्रम देता है कि वे चिकित्सकीय ORS खरीद रहे हैं, जबकि वह केवल सामान्य पेय होता है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को "मिसब्रांडेड" और "मिसलीडिंग" घोषित किया जाएगा और संबंधित कंपनियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की धारा 52 और 53 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आर्थिक दंड और जुर्माने के साथ-साथ उत्पादों के बाजार से हटाने की कार्रवाई भी शामिल होगी।

इस नए नियम के लागू होने के साथ ही FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे सख्ती से लागू करें और भ्रामक विज्ञापनों और झूठे दावों पर निगरानी बनाए रखें। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही जानकारी मिलेगी, बल्कि बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले के पीछे हैदराबाद की महिला डॉक्टर की लंबी और लगातार मेहनत है। उन्होंने पिछले आठ वर्षों से इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और FSSAI को लगातार सुझाव, अध्ययन और प्रमाण पेश किए। उनका कहना था कि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है कि चिकित्सा उत्पादों और सामान्य खाद्य/पेय उत्पादों के बीच स्पष्ट अंतर हो। डॉक्टर की इस लंबी लड़ाई ने अंततः उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण बदलाव की राह खोली और खाद्य उद्योग में पारदर्शिता और सुरक्षा के मानक को मजबूती प्रदान की।

इस फैसले के लागू होने के बाद अब कोई भी कंपनी ORS शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी और इस दिशा में FSSAI का लक्ष्य है कि बाजार में बेचे जाने वाले सभी पेय और फूड उत्पाद सुरक्षित, स्पष्ट और उपभोक्ता हितैषी हों। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय बच्चों और आम जनता के स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक महत्व का है और इसे लागू करने से उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

महाराष्ट्र में 500 मंदिर, 60 किले और 1800 जलस्रोतों का संरक्षण: मंत्री आशीष शेलार ने दी दिशा-निर्देश

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग 500 मंदिर, 60 संरक्षित किले और 1800 जलस्रोत शामिल हैं, जिन्हें संरक्षित करना और इनकी पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाना प्राथमिक लक्ष्य होगा। इस पहल का उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा करना है, बल्कि इनका सुचारु रखरखाव और पर्यटक आकर्षण बढ़ाकर सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना है।

सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि विस्तृत प्रारूप तैयार होने के बाद प्रत्यक्ष संवर्धन के लिए पर्याप्त निधि का प्रावधान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विचार किया जाए ताकि परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन में विविध संसाधनों का इस्तेमाल हो सके। बैठक में मित्र संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, सांस्कृतिक विभाग के सचिव किरण कुलकर्णी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक विशेष परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) बनाई जाएगी। इस इकाई में चार नए अधिकारी ठेके पर नियुक्त किए जाएंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से स्थलों की सुरक्षा, रखरखाव और संवर्धन के कामों का निरीक्षण करेंगे। मंत्री शेलार ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अलग नीति तैयार की जाएगी और निधि जुटाने के लिए विश्व बैंक समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्रोतों का अध्ययन किया जाएगा।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। यह संगठन नाशिक, पुणे और छत्रपति संभाजी नगर में ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों और किलों के संरक्षण और प्रचार-प्रसार का समग्र कार्य करेगा। संगठन का मुख्य उद्देश्य संबंधित जिलों में पर्यटन सुविधाओं का सुधार, स्थलों की सुरक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना होगा। इसके लिए स्थानीय अधिकारियों, पुरातत्व विभाग और मित्र संस्था की मदद ली जाएगी।

मंत्री ने बताया कि पहले चरण में मार्च 2026 तक पांच मंदिरों, पांच किलों और पांच जलस्रोतों के लिए डेस्टिनेशन मैनेजमेंट का कार्य शुरू किया जाएगा। इस पहल में संबंधित जिलाधिकारी, पुरातत्व विभाग और मित्र संस्था मिलकर विस्तृत योजना बनाएंगे और उसके कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। इस योजना के लागू होने से न केवल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित होगी, बल्कि यह पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का समग्र दृष्टिकोण राज्य के धरोहर स्थलों के दीर्घकालिक संरक्षण और बढ़ते सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

पत्नी को एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर मारने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, छह महीने बाद खुला हत्या का राज़

(जीएनएस)। बेंगलुरु। शहर के विक्टोरिया अस्पताल में कार्यरत गैस्ट्रो-सर्जन डॉ. महेंद्र रेड्डी को उनकी पत्नी और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. कृतिका एम. रेड्डी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी उस रहस्यमय मौत के लगभग छह महीने बाद हुई, जिसने चिकित्सा जगत को झकझोर कर रख दिया था। शुरू में इसे एक प्राकृतिक मौत माना जा रहा था, परंतु हाल ही में आई विसरा रिपोर्ट ने इस मामले की दिशा पूरी तरह बदल दी। पुलिस के अनुसार, 29 वर्षीय डॉ. कृतिका की मौत इस साल अप्रैल में हुई थी। उस समय उनके पति डॉ. महेंद्र ने बताया था कि पत्नी अचानक बेहोश हो गई थी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार को भी शुरुआत में शक नहीं हुआ, क्योंकि कृतिका पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं थीं और महेंद्र स्वयं डॉक्टर होने के नाते प्रारंभिक जानकारी वही दे रहे थे। लेकिन कुछ सप्ताह बाद जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, तब परिवार ने पुलिस से विस्तृत जांच की मांग की।

कृतिका के पिता के. मुनिरेड्डी, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, ने अपनी बेटी की मौत पर संदेह जताया और मराठाहल्ली थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि महेंद्र और उनकी बेटी के बीच पिछले कुछ महीनों से वैवाहिक विवाद चल रहा था। पिता का कहना है कि कृतिका ने कई बार बताया था कि महेंद्र का व्यवहार हिंसक हो गया है और वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। परिवार ने यह भी दावा किया कि कृतिका को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। इस शिकायत के बाद जब पुलिस ने विसरा जांच के लिए नमूने लैब भेजे, तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में पाया गया कि कृतिका के शरीर में प्रोपोफोल नामक शक्तिशाली एनेस्थीसिया ड्रग की अत्यधिक मात्रा थी। सामान्यतः यह दवा केवल ऑपरेशन थिएटर या इंटेंसिव केयर यूनिट में ही दी जाती है और उसकी मात्रा बेहद नियंत्रित होती है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि दी गई मात्रा "ओवरडोज़" की श्रेणी में आती है और यह सीधे तौर पर मृत्यु का कारण बन सकती है। जांचकर्ताओं ने बताया कि महेंद्र ने जानबूझकर यह दवा अपनी पत्नी को दी ताकि उसकी मौत को "नींद में आई हृदयगति रुकने" जैसी प्राकृतिक मौत की तरह दिखाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, महेंद्र को अस्पताल से प्रोपोफोल हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि वह स्वयं सर्जन था और उसे दवा तक सीधी पहुंच थी। उसने कृतिका को बेहोशी की दवा देने के बाद उसकी सांस रुकने का इंतजार किया और फिर ऐसा दिखाया जैसे वह अचानक बेहोश हो गई हो। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान महेंद्र खुद को निर्दोष बताता रहा। लेकिन जब विसरा रिपोर्ट ने उसकी कहानी को झूठा साबित किया, तो पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का विस्तार 17 अक्टूबर को

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का विस्तार 17 अक्टूबर को होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में मनोनीत मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर सुबह 11.30 बजे गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी इस समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के इस विस्तार में समाविष्ट होने वाले मनोनीत मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।